यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है- भजनलाल

इस विधेयक में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार देने व बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 22 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने "समान नागरिक संहिता विधेयक-2026" (यू.सी.सी. विधेयक) को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया है। संसदीय कार्यमंत्री डॉ. जोगाराम पटेल ने 21 अगस्त को यह विधेयक सदन में रखा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि 309 पन्नों और 403 धाराओं वाले इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, गोद लेने और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। यहां तक कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार देने तथा बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि, प्रस्तावित कानून के तहत जीवित जीवनसाथी के रहते दूसरा विवाह प्रतिबंधित और अमान्य होगा। विवाह के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

यूसीसी विधेयक-2026 में वसीयत, विरासत और पैतृक संपत्ति में विवाहित और अविवाहित बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने का प्रावधान है।

इस प्रस्तावित कानून में लिव-इन संबंध में रहने वाले जोड़ों के लिए संबंध शुरू करने और समाप्त करने की लिखित सूचना अथवा पंजीकरण का प्रावधान है। ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध संतान का दर्जा देने के साथ उन्हें माता-पिता की संपत्ति और भरण-पोषण में अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।

- **प्रस्तावित कानून में लिव-इन संबंध में रहने वाले जोड़ों के लिए संबंध शुरु करने और समाप्त करने की लिखित सूचना अथवा पंजीकरण का भी प्रावधान है।**

राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनकी पारंपरिक प्रथाओं, सांस्कृतिक पहचान और प्रथागत अधिकारों को संरक्षण मिलेगा।

राज्य सरकार के अनुसार, विधेयक के कानून बनने पर राजस्थान समान नागरिक संहिता लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा।

केन्द्र सरकार ने टीवी पर विज्ञापनों की समय सीमा हटाई

नई दिल्ली, 22 अगस्त। केन्द्र सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण की 12 मिनट की सीमा को खत्म कर दिया है। इस संबंध में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की गजट अधिसूचना 21 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई, जिसके साथ ही नया नियम प्रभावी हो गया।

- **वर्ष 2006 से टीवी पर विज्ञापनों की 12 मिनिट की समय सीमा लागू की गई थी।**

टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा वर्ष 2006 में लागू की गई थी। उस समय देश में केवल 62 टीवी चैनल थे। अब इनकी संख्या 900 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा केबल टीवी के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच केबल, जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बड़ी संख्या में चैनल उपलब्ध हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, टीवी उद्योग में अब पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है।

18 भाषाएं जानता है, ट्रेन में सामान बेचने वाला राजस्थानी वैंडर

एक्स पर एक यूज़र ने उक्त वैंडर का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह यात्रियों को टूथ ब्रश, टूथपेस्ट व साबून बेचते हुए तथा अलग-अलग भाषाओं में बात करता हुआ दिख रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अगस्त। ट्रेन में रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचने वाले एक व्यक्ति ने यात्रियों को उस समय हैरान कर दिया, जब उसने बताया कि वह 18 से 19 भाषाएं बोल सकता है और इनमें से कई भाषाएं उसने खुद सीखीं हैं।

- **उक्त वैंडर ने बताया कि वह राजस्थान का है तथा 18-19 भाषाएं बोल सकता है, ये सभी भाषाएं उसने खुद ही सीखी हैं।**
- **यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है और यूज़र्स उसकी खूब सराहना कर रहे हैं।**

एक्स यूज़र लक्ष्य मेहता ने इस मुलाकात का वीडियो साझा किया। वीडियो में यह व्यक्ति ट्रेन में यात्रियों के बीच टूथब्रश, टूथपेस्ट और साबुन बेचता और यात्रियों से बात करता नजर आ रहा है। वीडियो में वह एक यात्री टूथपेस्ट देता है। यात्री उससे उसके बारे में और उसकी भाषाओं की जानकारी के बारे में पूछने लगता है। व्यक्ति बताता है कि वह राजस्थान का रहने वाला है और 18 से 19 भाषाएं बोल सकता है।

इसके बाद वह यात्रियों से बातचीत करते हुए सहजता से अंग्रेजी में बोलने लगता है। उसकी धाराप्रवाह बातचीत से यात्री काफी प्रभावित नजर आते हैं।

उसने यह भी बताया कि उसे कई क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान है और उसने अलग-अलग भारतीय भाषाओं के बीच की समानताओं को भी बताया। भाषाओं के बीच संबंधों को पहचानने की उसकी क्षमता ने यात्रियों को खासा प्रभावित किया। वे उससे लगातार सवाल करते रहे और वह अपने भाषाओं के प्रति लगाव के बारे में बताता रहा।

बातचीत के दौरान यात्री उसके द्वारा बेचे जा रहे सामान से ज्यादा उसकी भाषाई प्रतिभा और सीखने की क्षमता में रुचि लेते नजर आए।

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि यह एक ऐसे व्यक्ति की झलक है, जो ट्रेन में टूथब्रश, टूथपेस्ट और साबुन बेचता है, 18-19 भाषाएं जानता है और नई भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को पसंद करता है।

वीडियो को दर्शकों से काफी सराहना मिली। कई लोगों ने कहा कि रोजी-रोटी के लिए मेहनत करते हुए इतनी भाषाएं सीखने की उसकी क्षमता वास्तव में प्रेरणादायक है।

कुछ लोगों का मानना था कि उसकी कहानी उस प्रतिभा और जिज्ञासा को सामने लाती है, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। वहीं अन्य लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, लगातार सीखते रहने के उसके जज्बे की तारीफ की।

कई यूज़र्स ने उसकी भाषाओं पर पकड़ और आत्मविश्वास की भी सराहना की। एक यूजर ने उसे लगातार सीखते रहने और कड़ी मेहनत करने की मिसाल बताया।

एक अन्य यूज़र ने कहा कि यह बातचीत उस भारत की तस्वीर पेश करती है, जिसे वह देखना चाहता है, जहां प्रतिभा, जिज्ञासा, विनम्रता और दृढ़ता एक साथ दिखाई देती हैं।

एसीडी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जांच के दौरान एजेंसी ने बड़ी संख्या में दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की तथा ठेकेदारों और विक्रेताओं से पूछताछ की। एसीबी जांच में सामने आया कि साल-2016 में आरोग्य रथ केवल कागजों में चलाया गया था। फर्जीवाड़े के समय नीरज के. पवन एनएचएम में पदस्थापित थे।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अर्थ, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को पहुंचाने के लिए अभियान शुरू करेगी।

उन्होंने कहा, "भाजपा पूर्ण वंदे मातरम् के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा करेगी।"

भाजपा महात्मा गांधी के उस बयान को भी प्रचारित करेगी, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम् को साम्राज्यवाद-विरोधी नारा बताते हुए, इसे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बताया था।

नबीन ने कहा, सत्तारूढ़ दल ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है, ताकि छह अंतरों वाले पूर्ण राष्ट्रीय गीत और उसके इतिहास को भुलाया न जाए और आने वाली पीढ़ियां वंदे मातरम् से जुड़ी भारत की स्वतंत्रता की यादों और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझ सकें।

अजीब है खेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जारी की गई हो, तो यह समारोह नहीं होता। राष्ट्रपति भवन के अनुसार, चेंज ऑफ गार्ड एक सैन्य परंपरा है, जिसके तहत महलों, किलों और रक्षा प्रतिष्ठानों में तैनात गार्ड और संतरी समय-समय पर बदले जाते हैं, ताकि सैनिकों की नई टुकड़ी जिम्मेदारी संभाल सके।

बताया गया था कि रहमान की भारत यात्रा 23 और 24 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ मुद्दों के कारण यह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका।

विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि भारत ने रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के साथ-साथ, नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है।

इस महत्वपूर्ण यात्रा के कार्यक्रम और अन्य पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की राजनयिक बातचीत भी हुई है।

दोनों देशों के संबंधों में हाल में उस समय कुछ और तनाव पैदा हुआ, जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को नई दिल्ली से वर्चुअल मीडिया संवाद किया।

हसीना के इस संवाद के बाद, ढाका ने एक बार फिर उनके प्रत्यर्पण की मांग दोहराई और यहां तक कि इसे रहमान की संभावित भारत यात्रा से जोड़ने की कोशिश भी की।

मीडिया संवाद के बाद, भारत ने खुद को उससे अलग करते हुए स्पष्ट किया कि नई दिल्ली ने न तो इसमें कोई भूमिका निभाई थी और न ही हसीना की टिप्पणियों का समर्थन किया था।

78 वर्षीय हसीना को अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। वे उसी वर्ष 5 अगस्त को ढाका से निकलने के बाद से भारत में रह रही हैं।

पाकिस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के तहत, संतुलित विदेश नीति पर आगे बढ़ रहा है। इसमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बांग्लादेश की ओर से आए ताजा संकेतों के बाद मक्का रक्षा समझौते के संभावित विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि, ढाका ने अभी औपचारिक रूप से इस समझौते में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। बावजूद इसके, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच उभरते नए रणनीतिक समीकरणों पर भी नजरें टिक गई हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 9 अगस्त को कहा था कि मक्का समझौता उन देशों के लिए खुला है, जो इसके मूल सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि यह समझौता रक्षात्मक उद्देश्य से किया गया है और इससे पाकिस्तान के मौजूदा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों को रद्द या प्रभावित नहीं किया गया है।

महिलायें अधिक संवेदनशील, सौम्य, दयालु व दूरदर्शी होती हैं- राहुल गांधी

उन्होंने पुणे में "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम में अपने विचार रखे

पुणे, 22 अगस्त। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं स्वभाव से पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील, सौम्य, दयालु और दूरदर्शी होती हैं और इसीलिए मेरा मूल रूप से मानना है कि भारत की महिलाएं देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जब भी मैं किसी पुरुष से बात करता हूं, तो महिलाओं को तीन श्रेणियों में रखा जाता है।

- **राहुल गांधी ने महिलाओं से कहा कि पिता, भाई, पति या बेटे के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी संपत्ति नहीं हैं, आप अपनी खुद की हैं।**

उन्हें बेटी, पत्नी या मां के रूप में देखा जाता है। पत्नी, बेटी या मां के रूप में देखे जाने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह आपकी एकमात्र पहचान नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास शानदार महिलाएं हों. जो बेहद दिलचस्प और अलग-अलग काम कर रही हों, जो प्रौफैशनल हों, खिलाड़ी हों, कई तरह के काम करती हों, और फिर भी हमारे पुरुषों द्वारा उन्हें केवल इन्हीं तीन रूपों में पहचाना जाए।

राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मनुस्मृति कहती है- बचपन में महिला अपने पिता की होती है। जवानी में वह अपने पति की होती है। पति की मृत्यु के बाद वह अपने बेटों की होती है।

महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। यह मनुस्मृति का सीधा उद्धरण है और ये शब्द शर्मनाक हैं, क्योंकि ये शब्द कभी कहे ही नहीं जाने चाहिए थे।

राहुल गांधी ने कहा, मेरा मानना है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारी महिलाएं स्वतंत्र हों, अपने लिए खड़ी हों और खुद पर भरोसा रखें। पिता, भाई, पति या बेटे के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी संपत्ति नहीं हैं। आप अपनी खुद की हैं।

पुणे में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसे लेकर मैं बिल्कुल साफ हूं। उन्होंने कहा कि यह 70 करोड़ महिलाओं की अनोखी यात्राएं और अनोखे सपने हैं, जिन्हें वे जी रही हैं।

इस कार्यक्रम से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा विधायक राम कदम ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में छात्रों को पैसे देकर लाया जा रहा है। तो जो लोग पैसे लेकर कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनसे किस तरह का संवाद होगा। राहुल गांधी को सुनने कोई नहीं आ रहा, वे पैसे मिलने की वजह से आ रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस नेता यशोमति चंद्रकांत ठाकुर ने इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, आप भाजपा के अकाउंट देखिए और हमारे अकाउंट देखिए। हमारे पास पैसा आएगा कहां से? हमारे पास पैसा ही नहीं है। कांग्रेस उत्साह से भरी है, बच्चे उत्साह से भरे हैं। कोई डरा हुआ नहीं है।

बार काउन्सिल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसे मनन कुमार मिश्रा का लगातार सातवां कार्यकाल बता रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि बीसीआई रुल्स के रुल 12(2) में चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के लिए दो साल के कार्यकाल या सदस्यता खत्म होने तक का प्रावधान है। याचिका में कहा गया है कि कोई प्रशासनिक नोटिफिकेशन नियमों द्वारा तय सीमा से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ा सकता है।

प्रधानमंत्री ने भाजपा की नयी कार्यकारिणी के साथ बैठक की

नयी दिल्ली, 22 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों से बातचीत की और कहा कि ऐसी बैठकें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नए विचारों तथा दृष्टिकोण पर केन्द्रित होती हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व वाली नयी टीम की घोषणा 17 अगस्त को की गई थी और टीम ने पहली बार पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। बैठक में निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी और कुछ राज्य इकाइयों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, संगठन की बैठकें पार्टी को मजबूत बनाने और लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए नए विचारों व नजरिए पर केन्द्रित होती हैं। पार्टी के साथियों और नयी संगठनात्मक टीम के साथ बहुत सार्थक बातचीत हुई। बैठक में भाजपा के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राम माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, महासचिव (संगठन) बी. एल. संतोष और कोषाध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। भाजपा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी ने पार्टी की नवनियुक्त संगठनात्मक टीम से बातचीत की और पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाने तथा लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए अपने विचार और दृष्टिकोण साझा किये।

'डीडीए" आर्ट ऑफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह भी कहा कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में डीडीए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा।

अदालत ने शहरी नियोजन एवं विकास संस्था को एनजीटी के निर्देश के अनुरूप यमुना के बाढ़ क्षेत्र के पुनर्वास का काम जारी रखने का भी निर्देश दिया।

एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को यमुना के किनारे विशाल आयोजन करने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि संगठन पर्यावरण को हुए नुकसान की पूरी राशि जमा करेगा। यह कार्यक्रम "11 से 13 मार्च 2016" के बीच आयोजित हुआ था।

11 मार्च 2016 को "वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल" के उद्घाटन के दिन आयोजकों ने एनजीटी के समक्ष आवेदन देकर पूरी राशि जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था।

ट्रिब्यूनल ने उस दिन फाउंडेशन को 25 लाख रुपये जमा करने की अनुमति दी और शेष राशि जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

आर्ट ऑफ लिविंग ने तत्काल 25 लाख रुपये जमा कर दिए। बाद में उसने शेष 4.75 करोड़ रुपये को राशि जमा करने के बजाय बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करने और उस धन का इस्तेमाल क्षेत्र में जैव विविधता पार्क स्थापित करने के लिए करने का अनुरोध किया, लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं की गई। बाद में जुर्माने की पूरी राशि जमा कर दी गई, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ने एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके साथ ही, इस मामले में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जो लंबे समय तक चली।

उत्तर प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उम्मीदवारों और ऐसे स्थानीय मुद्दों, जो मतदाताओं के रुख को प्रभावित कर सकते हैं, पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

सर्वेक्षणों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर भाजपा संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के साथ-साथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति का आकलन करेगी, ताकि चुनावी अभियान के पूरी तरह गति पकड़ने से पहले रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके।

फूड इकॉनमी तेजी से बढ़ रही ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले कीड़ों को निकाल दिया जाएगा।

हालांकि, महाराष्ट्र के इस अनुभव को इस बात के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा की समस्या केवल इसी राज्य में है।

राष्ट्रीय स्तर पर खाने के स्टैण्डर्ड "फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" (एफएसएसएआई) द्वारा तय किए जाते हैं, जबकि इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की होती है। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि नियमों का पालन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है।

- **विशेषज्ञों ने फूड सेफ्टी में भारी सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के मंजूर किए गए हर तीन में से एक पद खाली हैं। ऐसे में इतने बड़े खाद्य बाज़ार का लगातार निरीक्षण करना मुश्किल हो जाता है।**

2025-26 में उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, राज्यों ने 2.24 लाख से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की, जिनमें से 40,000 से अधिक नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, यानी लगभग 18 प्रतिशत। महाराष्ट्र में जांच किए गए 7,694 नमूनों में से 1,335 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

राज्यों के बीच ये आंकड़े काफी अलग-अलग हैं और इन्हें खाद्य सुरक्षा की सीधी रैंकिंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि जांच की तीव्रता, लिए गए खाद्य नमूनों के प्रकार और नियम लागू करने के तरीके अलग-अलग हैं। लेकिन ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि खाद्य सुरक्षा के उल्लंघन की समस्या केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत की फूड इकॉनमी के आकार और नियम लागू करने की क्षमता के बीच अंतर है। जून 2026 तक भारत में 74 लाख से अधिक सक्रिय खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण थे। लेकिन 2025-26 की तीसरी तिमाही तक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्वीकृत 4,208 पदों में से केवल 2,997 पद भरे हुए थे, यानी करीब 29 प्रतिशत पद खाली थे।

रेस्तरां, क्लाउड किचन, खाद्य डिलीवरी प्लेटफॉर्म, क्विक-कॉमर्स के गोदामों, सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों और छोटे खाद्य कारोबारों की तेजी से बढ़ती संख्या ने समस्या को और बढ़ा दिया है। अब नियमों को ऐसे लाखों अतिरिक्त स्थानों पर लागू करना पड़ रहा है, जहाँ खाद्य पदार्थों को स्टोर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और बेचा जा सकता है।

चुनौती केवल खाद्य पदार्थों में मिलावट से कहीं ज्यादा बड़ी है। कोई उत्पाद प्रयोगशाला के मानकों पर खरा उतर सकता है, लेकिन दूषित पानी, खराब रेफ्रिजरेशन, कीड़ों की मौजूदगी, गलत तरीके से स्टोर करने या साफ-सफाई न रखने के कारण वह असुरक्षित हो सकता है।

विशेषज्ञों और नियामक अधिकारियों का मानना है कि भारत को धीरे-धीरे ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ने की जरूरत है, जो मुख्य रूप से शिकायत, निरीक्षण, नोटिस और जुर्माने पर आधारित प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था के बजाय, जोखिम के आधार पर पहले से रोकथाम करने वाली व्यवस्था हो।

अधिक जोखिम वाले प्रतिष्ठानों में ज्यादा बार और अचानक निरीक्षण होना चाहिए, जबकि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, सस्पैंशन और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं पर भी छोटे प्रतिष्ठानों की तरह ही खाद्य सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण सुधार अधिक पारदर्शिता लाना हो सकता है। रैस्तरां, होटल, क्लाउड किचन और खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए उनके एफएसएसएआई लाइसेंस से जुड़े डिजिटल फूड सेफ्टी स्कोरकार्ड बनाए जा सकते हैं। इनमें निरीक्षण की तारीख, गंभीर कमियां, लगाए गए जुर्माने और कमियों को दूर किया गया या नहीं, इसकी जानकारी दी जा सकती है। उपभोक्ता इस जानकारी को क्यूआर कोड के जरिए देख सकते हैं।

हालांकि, तत्काल चुनौती कर्मचारियों की कमी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के मंजूर किए गए हर तीन में से एक पद खाली है, जिससे इतने बड़े और विविध खाद्य बाजार में लगातार निरीक्षण करना मुश्किल हो जाता है।

इसलिए महाराष्ट्र में हुई कार्रवाई ने एक राष्ट्रीय नीति से जुड़ा सवाल सामने रखा है। भारत को फूड सेफ्टी के नियमों की एक और परत की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी पहले से मौजूद नियमों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है।

असल परीक्षा यह होगी कि क्या मौजूदा मुहिम से लंबे समय तक चलने वाले संस्थागत बदलाव आते हैं या यह केवल कुछ अधिकारियों और अस्थायी अभियानों पर निर्भर रहती है। फूड सेफ्टी को अंततः एक रैगुलर पब्लिक हैल्थ फंक्शन बनाना होगा, जिसे पर्याप्त कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं, तकनीक, पारदर्शी निरीक्षण और बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए कड़े जुर्माने का समर्थन मिले।

सीजेपी-ग्रामीण विवाद के 24 घंटे में रामपुर-कंवरपुरा स्कूल 50 मीटर दूर शिफ्ट हुआ

नए स्थान पर 16 बच्चे पढ़ने पहुँचे, पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज की

जयपुर, 22 अगस्त। बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में राजकीय प्राथमिक स्कूल के निरीक्षण को लेकर शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच हुआ विवाद शनिवार को भी जारी रहा। दोनों पक्षों ने शिवदासपुरा थाने में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत करके मारपीट और हुड़दंग के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाद के करीब 24 घंटे बाद, शनिवार सुबह स्कूल को पुरानी जर्जर इमारत से करीब 50 मीटर दूर गांव के एक भवन में शिफ्ट कर दिया गया। यहां 16 से अधिक बच्चे पढ़ने पहुंचे।

- **सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने कहा कि सीजेपी ने घटना से संबंधित वीडियो सार्वजनिक कर दिए हैं। उन्होंने दूसरे पक्ष के भी वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की।**
- **बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने शनिवार शाम को ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए राशि जारी की है, जिससे बगरू विधानसभा क्षेत्र के 60 विद्यालयों में काम कराया गया है।**

एसीपी चाकसू भवानी सिंह ने बताया कि सीजेपी की टीम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने रामपुरा-कंवरपुरा पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसमें मारपीट की स्थिति बनी। दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीजेपी के सह-संयोजक एवं प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि उनकी टीम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। लेकिन गांव में पहुंचते ही उन्हें रोक दिया गया। रांका के अनुसार, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, पथराव हुआ, वाहनों के शीशे तोड़े गए और कुछ कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। उन्होंने इसे सुनियोजित हमला बताते हुए आरोप लगाया कि बाहर से लोगों को बुलाया गया था।

रांका ने दावा किया कि घटना में शामिल बताए जा रहे कुछ लोग बाद में स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने घटना से संबंधित वीडियो सार्वजनिक किए हैं और दूसरे पक्ष से भी उपलब्ध वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीजेपी के लोग बड़ी संख्या में गांव पहुंचे और स्कूल निरीक्षण के नाम पर ग्रामीणों से विवाद किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके आने से गांव का माहौल खराब हुआ और बच्चों में डर पैदा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हथियार लेकर आए थे और ग्रामीणों को डराया-धमकाया गया।

ग्रामीण रविशंकर शर्मा के अनुसार, गांववालों की सहमति से भवन स्कूल संचालन के लिए उपलब्ध कराया गया है। यहां पहले किराना की दुकान चलती थी। अब इसी भवन में बच्चों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। मौके पर दो शिक्षक भी बच्चों के साथ मौजूद थे।

हालांकि नए स्थान पर भी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि गांव में स्कूल के स्थायी भवन का जल्द निर्माण या मरम्मत कार्य कराया जाए।

बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने शनिवार शाम को रामपुरा गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की।

वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी विद्यालयों में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए राशि जारी की है और बगरू विधानसभा क्षेत्र में 60 से अधिक स्कूलों में काम कराया गया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908